राज्य (एसपीई हैदराबाद)

बनाम

एयर कमोडोर कैलाश चंद

21 दिसंबर, 1979

[एस. मुर्तजा फजल अली, पी.एस. कैलासम और ए.डी. कौशल, जेजे.]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 11), धारा 5(2) – वायु सेना अधिकारी सेवा से सेवानिवृत्त - सेवाएँ नियमित वायु सेना रिज़र्व में स्थानांतरित कर दी गईं - अधिनियम के तहत अधिकारी पर अभियोजन - अधिकारी यदि कोई लोक सेवक है – क्या मंजूरी आवश्यक है ।

भारतीय वायु सेना के एक सदस्य, प्रत्यर्थी 15 जून, 1965 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन 16 जून, 1965 से दो साल की अवधि के लिए उन्हें फिर से नियुक्त किया गया। 7 सितंबर, 1966 को प्रत्यर्थी को 16 जून, 1965 से 15 जून, 1970 यानी पांच साल की अवधि के लिए नियमित वायु सेना रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया। 13 मार्च 1968 को प्रत्यर्थी को दी गई पुनर्नियुक्ति बंद हो गई और 1 अप्रैल, 1968 से उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। 29 मार्च, 1965 से 16 मार्च, 1967 की अवधि के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(2) के तहत अपराध करने के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रत्यर्थी ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष इस आधार पर उसके खिलाफ कार्यवाही को ड्राप करने के लिए याचिका दायर की कि न्यायाधीश प्रत्यर्थी के नियुक्ति प्राधिकारी की किसी भी वैध मंजूरी के अभाव में अपराधों का कोई संज्ञान नहीं ले सकता है। आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि चूंकि प्रत्यर्थी उस समय वायु सेना में कमीशन प्राप्त

अधिकारी नहीं था जब संज्ञान लिया गया था, इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी।

प्रत्यर्थी ने पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने कार्यवाही को रद्द कर दिया, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि चूंकि प्रत्यर्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर एक लोक सेवक बना रहा क्योंकि वह वायु सेना रिजर्व का सदस्य बना रहा, इसलिए प्रत्यर्थी पर अभियोजन चलाने से पहले मंजूरी आवश्यक थी।

इस न्यायालय में की गई अपील में, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया थाः (1) क्योंकि प्रत्यर्थी भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त हो गया था और उसकी नौकरी 1 अप्रैल, 1968 से समाप्त कर दी गई थी, इसलिए वह एक लोक सेवक नहीं रह गया था और इसलिए कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी, और (2) नियमित वायु सेना रिज़र्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुनः नियुक्ति सेवा के नियमित बल में रोजगार के बराबर नहीं होगी और इसलिए भले ही प्रत्यर्थी को फिर से नियुक्त किया गया हो, उसे लोक सेवक का दर्जा रखने वाला नहीं कहा जा सकता था।

अपील को खारिज करते हुए-

अभिनिर्धारित किया: 1. अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि जिस समय अपराध का संज्ञान लिया गया था, उस समय प्रत्यर्थी का लोक सेवक होना समाप्त हो गया था। [700 सी]

तत्काल मामले में विशेष न्यायाधीश ने 19 जून, 1969 को संज्ञान लिया, एक ऐसे समय में जब प्रत्यर्थी को फिर से नियुक्त किया गया था और हालांकि उनकी सेवाओं को केवल 1 अप्रैल, 1968 को समाप्त कर दिया गया था, वह 15 जुलाई, 1970 तक सहायक वायु सेना के सदस्य बने रहे, जो अपराध का संज्ञान लेने के लंबे समय बाद है। [700 डी]

एस. ए. वेंकटरमण अन्य राज्य [1958] एस.सी.आर. 1037; पश्चिम बंगाल राज्य आदि बनाम मनमल भूटोरिया और अन्य आदि [1977] 3 एस.सी.आर. 758 संदर्भित।

2(i) सहायक वायु सेना अधिनियम के प्रावधानों में प्रत्यर्थी को मिलने वाले परिलब्धियों की प्रकृति स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है, लेकिन सामान्य अवधि और अधिनियम की स्थापना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सहायक बल का एक सदस्य उतना ही लोक सेवक है जितना कि भारतीय वायु सेना का एक कार्यवाहक सदस्य। [703 जी]

(ii) सहायक वायु सेना में प्रत्यर्थी के स्थानांतरण के बाद भी उन्होंने एक लोक सेवक के रूप में अपना चरित्र बनाए रखा क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण से गुजरना था और आवश्यकता पड़ने पर सेवा के लिए बुलाया जाना था। [703 एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 259/1973

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण मामला संख्या 72/73 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27-4-1973 से उत्पन्न।

आर. बी. दातार, एम. एन. श्रॉफ और आर. एन. सचथी, अपीलार्थी की ओर से ।

पी. गोविंदन नायर और ए. सुब्बा राव, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

फजल अली, न्यायाधिपति

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 27 अप्रैल 1973 के निर्णय के खिलाफ प्रमाण पत्र द्वारा अपील का निर्देश दिया गया है, जिसमें पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार किया

गया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत किए गए अपराधों के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है।

मामले में हम जो दृष्टिकोण रखते हैं, उसमें तथ्यों को विस्तार से देना आवश्यक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी भारतीय वायु सेना का एक सदस्य था जिसने 7 नवंबर 1941 को सेवा में प्रवेश किया था। वे 15 जून 1965 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए लेकिन 16 जून 1965 से दो साल की अवधि के लिए उन्हें फिर से नियुक्त किया गया। 7 सितंबर 1966 को प्रत्यर्थी को 16 जुलाई 1965 से 15 जून 1970 यानी पांच साल की अवधि के लिए नियमित वायु सेना रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी को सहायक रिज़र्व वायु सेना अधिनियम 1952 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत सहायक आरक्षित वायु सेना में स्थानांतरित कर दिया गया था। 13 मार्च 1968 को प्रत्यर्थी को दी गई पुनर्नियुक्ति बंद हो गई और 1 अप्रैल 1968 से उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया।

27 मार्च, 1965 से 16 मार्च, 1967 की अवधि के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत अपराध करने के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रत्यर्थी ने विशेष न्यायाधीश, हैदराबाद के समक्ष अपने खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक याचिका इस आधार पर दायर की कि प्रतिवादी के नियुक्ति प्राधिकारी की किसी वैध मंजूरी के अभाव में न्यायाधीश अपराधों का कोई संज्ञान नहीं ले सकता। हालाँकि, विशेष न्यायाधीश ने 20 अक्टूबर 1972 को इस आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी उस समय वायु सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी नहीं था जब संज्ञान लिया गया था, इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद, प्रत्यर्थी ने पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय का रुख किया और उच्च न्यायालय के समक्ष सफल हुआ जिसने यह अभिनिर्धारित

किया कि चूंकि प्रत्यर्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर एक लोक सेवक बना रहा क्योंकि वह वायु सेना रिजर्व का सदस्य बना रहा, इसलिए प्रत्यर्थी पर अभियोजन चलाने से पहले मंजूरी आवश्यक थी। उच्च न्यायालय ने तदनुसार पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, लेकिन इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए अपीलकर्ता को प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया। इसलिए यह अपील हमारे समक्ष है।

हमारे सामने केवल एक ही बात का प्रचार किया गया है कि क्या प्रत्यर्थी भारतीय वायु सेना की सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी एक लोक सेवक बना रहा, भले ही उसे नियमित वायु सेना रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया हो। संघ के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि प्रत्यर्थी भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त हो गया था और उसकी पुनर्नियुक्ति 1 अप्रैल, 1968 से समाप्त कर दी गई थी, इसलिए वह एक लोक सेवक नहीं रह गया और इसलिए, किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। हमने पक्षों के अधिवक्ता को सुना है और उच्च न्यायालय और विशेष न्यायाधीश के फैसले पर भी विचार किया है। ऊपर वर्णित तथ्य विवादित नहीं हैं और इस मामले में दो प्रश्न निर्धारित किए जा सकते हैं।

सबसे पहले, यह तय करना होगा कि प्रत्यर्थी 27-3-65 से 16-3-67 की अवधि के दौरान लोक सेवक था या नहीं। दूसरा, वह समय क्या है जब मंजूरी आवश्यक थी, अर्थात वह समय जब अपराध वास्तव में किए गए थे या जब न्यायालय ने उक्त अपराधों का संज्ञान लिया था। हम पहले दूसरा मुद्दा उठाएंगे। एस.ए. वेंकटरमण बनाम राज्य [(1)] के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए एक समान प्रश्न सामने आया, जिसमें न्यायालय ने इमाम न्यायाधिपति. द्वारा बोलते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

"हमारी राय में, अधिनियम की धारा 6 में उपयोग किए गए शब्दों के सामान्य अर्थ को प्रभावी बनाने के लिए, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि जिस समय एक न्यायालय को संज्ञान लेने के लिए कहा जाता है, न केवल एक लोक सेवक द्वारा अपराध किया गया होना चाहिए, बल्कि अभियुक्त व्यक्ति अभी भी एक लोक सेवक है जिसे धारा 6 के प्रावधानों के लागू होने से पहले एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।"

इस मामले के बाद पश्चिम बंगाल राज्य आदि बनाम मनमल भूटोरिया और अन्य इत्यादि [(1)] के मामले में इस न्यायालय का नया निर्णय आया, जिसमे पिछले निर्णय का अनुसरण किया गया। ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, मामला अब एकीकृत नहीं है, बल्कि इस न्यायालय के निर्णयों से समाप्त होता है। इसलिए, यह निम्न है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना चाहिए कि जिस समय अपराध का संज्ञान लिया गया था, उस समय प्रत्यर्थी का लोक सेवक होना समाप्त हो गया था। तत्काल मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष न्यायाधीश ने 19 जून, 1969 को ऐसे समय में संज्ञान लिया था जब प्रत्यर्थी को फिर से नियुक्त किया गया था और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि उसकी सेवाओं को केवल 1-4-1968 पर समाप्त कर दिया गया था, लेकिन वह 15-6-70 तक सहायक वायु सेना का सदस्य बना रहा, यानी अपराध का संज्ञान लेने के लंबे समय बाद भी। हालाँकि, संघ के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियमित वायु सेना रिज़र्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुनर्नियुक्ति सेवा के नियमित बल में नियुक्ति के बराबर नहीं होगी और इसलिए भले ही प्रत्यर्थी को पुनर्नियुक्ति दी गई हो, लेकिन उसे लोक सेवक का दर्जा रखने वाला नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में, प्रत्यर्थी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के बाद रखे गए रोजगार की प्रकृति को दिखाने के लिए कुछ नियम हमारे सामने रखे गए हैं। यह

विवादित नहीं है कि पुनर्नियुक्ति के बाद भी, प्रत्यर्थी को वायु सेना सहायक रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया था और सहायक वायु सेना रिजर्व का सदस्य बना रहा। अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ हैं। नीचे निकाला गयाः -

"4. नियमित वायु सेना रिजर्व का गठन -केंद्र सरकार इस अध्याय में इसके बाद के तरीके से नियमित वायु सेना रिजर्व नामित करने के लिए एक वायु सेना रिजर्व का निर्माण और रखरखाव कर सकती है, जिसमें धारा 5 के तहत केवल स्थानांतरित या नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।

5. नियमित वायु सेना रिजर्व में भर्ती- (1) सक्षम प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियमित वायु सेना रिजर्व को स्थानांतरित कर सकता है -

(क) वायु सेना का कोई भी अधिकारी या वायुसैनिक जो अपनी सेवा के नियमों और शर्तों के तहत किसी भी वायु सेना रिजर्व में सेवा करने के लिए उत्तरदायी है यदि और जब गठित किया जाता है;

(बी) वायु सेना का कोई भी अधिकारी या वायुसैनिक जिसका वायु सेना में कमीशन या नियुक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले समाप्त कर दी गई है और जो अपने कमीशन या नियुक्ति की शर्तों के तहत किसी भी वायु सेना रिजर्व में सेवा करने के लिए उत्तरदायी था यदि और जब गठित किया गया था;

(ग) कोई भी अधिकारी या वायुसैनिक जिसने वायु सेना में सेवा की है और वहां से सेवानिवृत्त हुआ है;

और इस तरह से स्थानांतरित किसी भी अधिकारी या वायुसैनिक को उक्त रिजर्व का सदस्य माना जाएगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जाएं, विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के तहत बनाए गए और बनाए रखे गए वायु रक्षा रिजर्व या सहायक वायु सेना के किसी भी सदस्य को नियमित वायु सेना रिजर्व में नियुक्त कर सकता है, और जहां ऐसा कोई सदस्य इस तरह से नियुक्त किया जाता है, वह वायु रक्षा रिजर्व या सहायक वायु सेना का सदस्य नहीं रहेगा, और ऐसी नियुक्ति की तारीख से नियमित वायु सेना रिजर्व का सदस्य माना जाएगा।

(3) .....

6. नियमित वायु सेना रिजर्व में व्यक्तियों के वर्ग-नियमित वायु सेना रिजर्व के सदस्यों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात्ः -

(क) सामान्य कर्तव्य अधिकारी, और

(ख) जमीनी कर्तव्य वाले अधिकारी, और

(ग) वायुसैनिक,

और प्रत्येक अधिकारी रिजर्व में स्थानांतरण या नियुक्ति पर उसी पद को धारण करने का हकदार होगा जो वह वायु सेना या वायु रक्षा रिजर्व या सहायक वायु सेना में, जैसा भी मामला हो, ऐसे स्थानांतरण या नियुक्ति से पहले रखता था।

7. सेवा की अवधि-(1) नियमित वायु सेना रिजर्व का प्रत्येक सदस्य रिजर्व में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा -

(क) यदि उसे धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत रिजर्व में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसके दायित्व की अवधि के लिए; और

(ख) यदि वह धारा एस की उप-धारा (2) के तहत रिजर्व में नियुक्त किया जाता है, तो शेष अवधि के लिए जिसके लिए वह वायु रक्षा रिजर्व या सहायक वायु सेना में सेवा करने के लिए उत्तरदायी था, जैसा भी मामला होः

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी भी सदस्य से रिजर्व में ऐसी आगे की अवधि या कुल पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए सेवा करने की अपेक्षा कर सकता है जो वह उचित समझे।

x x x x x

9. वायु रक्षा रिजर्व का गठन-केंद्र सरकार इस अध्याय में वायु रक्षा रिजर्व नामित करने के लिए एक वायु सेना रिजर्व का प्रावधान करने के बाद इस तरीके से निर्माण और रखरखाव कर सकती है, जिसमें धारा 16 के प्रावधानों के तहत नामांकित व्यक्ति शामिल होंगे।

10. वायु रक्षा रिजर्व में व्यक्तियों के वर्गों-वायु रक्षा रिजर्व के सदस्यों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात्ः -

(क) सामान्य कर्तव्य अधिकारी;

(बी) जमीनी कर्तव्य अधिकारी; और

((ग) वायुसैनिक।

x x x x x

12. जाँच के लिए बुलाए जाने की देयता-प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 11 के प्रावधान लागू होते हैं, धारा 13 के तहत जाँच के लिए बुलाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(क) यदि वह धारा 11 की उप-धारा (1) के धारा (क) से धारा (च) में निर्दिष्ट किसी वर्ग से संबंधित है, जब तक कि वह अपना सैंतीसवां वर्ष पूरा नहीं कर लेता है, और

(बी) यदि वह उक्त उप-धारा के धारा (जी) और (एच) में निर्दिष्ट किसी भी वर्ग से संबंधित है, जब तक कि वह अपना पचासवां वर्ष पूरा नहीं कर लेता है।

x x x x x

18. सहायक वायु सेना का गठन-(1) केंद्र सरकार इस अध्याय में इसके बाद के तरीके से सहायक वायु सेना नामित करने के लिए एक वायु सेना का गठन और रखरखाव कर सकती है।

(2) केंद्र सरकार सहायक वायु सेना की इतनी संख्या में स्क्वाड्रनों और इकाइयों का गठन कर सकती है जो वह उचित समझे और किसी भी स्क्वाड्रन या इकाई को भंग या पुनर्गठित कर सकती है।

19. सहायक वायु सेना में व्यक्तियों के वर्गों-सहायक वायु सेना के सदस्यों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात्ः

(क) सामान्य कर्तव्य अधिकारी;

(बी) जमीनी कर्तव्य अधिकारी; और

((ग) वायुसैनिक।

20. सहायक वायु सेना के अधिकारी-राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को सहायक वायु सेना में एक अधिकारी के रूप में एक कमीशन प्रदान कर सकता है जो वह वायु सेना में किसी भी कमीशन अधिकारी के पदनाम के साथ उचित समझता है।

.....

22. सेवा की अवधि -प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को, इस अधिनियम के तहत इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, अपनी नियुक्ति या नामांकन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए सहायक वायु सेना में सेवा करने की आवश्यकता होगी, लेकिन अपनी सेवा की अवधि पूरी होने के बाद, पांच साल से अधिक की अवधि की आगे की अवधि के लिए उसमें सेवा करने के लिए स्वेच्छा से काम कर सकता है।

23. सेवा समाप्ति -सहायक वायु सेना में किसी भी अधिकारी या नामांकित व्यक्ति की सेवा, उसकी सेवा की अवधि पूरी होने से पहले किसी भी समय, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी शर्तों के तहत समाप्त की जा सकती है जो निर्धारित की जा सकती हैं।" (हमारा जोर)

इन धाराओं के प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक बार जब प्रत्यर्थी को सहायक वायु सेना में स्थानांतरित कर दिया गया तो उसने एक

लोक सेवक के रूप में अपना चरित्र बनाए रखा क्योंकि उसे प्रशिक्षण से गुजरना था और आवश्यकता पड़ने पर सेवा के लिए बुलाया जाना था। यह सच है कि इन प्रावधानों में प्रत्यर्थी को प्राप्त होने वाले परिलब्धियों की प्रकृति स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है, लेकिन अधिनियम की सामान्य अवधि और स्थापना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सहायक बल का एक सदस्य उतना ही लोक सेवक है जितना कि भारतीय वायु सेना का एक कार्यवाहक सदस्य। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया है और हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। इस मामले में यह विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थी पर अभियोजन चलाने से पहले नियुक्ति प्राधिकरण से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। इन कारणों से, हम उच्च न्यायालय के फैसले में कानून की कोई त्रुटि नहीं पाते हैं और अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

एन.वी.के.

अपील खारिज की गई।

(1) [1958] एस.सी.आर. 1037 पेज 3

(1) [1977] 3 एस.सी.आर. 758 पेज 4

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****